“दलित समाज में राजनैतिक चेतना”

(विशेष संदर्भ : उत्तर प्रदेश)

एम. फिल. उपाधि हेतु

लघु शोध-प्रबंध

(सत्र: 2011-2012)

ज्ञान शांति मैत्री

शोध-निर्देशक

प्रो. एल कारुण्यकरा

निदेशक, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर दलित एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र

शोधार्थी

राजकुमार

एम.फिल. दलित एवं आदिवासी अध्ययन

Reg. No. 2011/03/203/001

संस्कृति विद्यापीठ

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर दलित एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442005 (महाराष्ट्र)

भूमिका

लोकतांत्रिक समाजों में राजनीति को सामाजिक विषमता और आर्थिक शोषण से मुक्ति पाने के सशक्त माध्यम के रूप में जाना जाता है लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में मनुष्य को समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अधिकार प्रदान करने का दावा करता है। और लोकतंत्र को जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन कहा जाता है परंतु प्रश्न यह उठता है कि यह लोकतंत्र का भोक्ता कर्ता और निर्माता होगा कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र में राजनीति व्यवस्था में भागीदारी ही नहीं बल्कि समाज के उस वर्ग की पहचान आवश्यक है जो लोकतंत्र को नियंत्रित करने की ताकत रखता है। कहना न होगा कि भारतीय समाज में आजादी के बाद आए लोकतंत्र को नियंत्रित करने की ताकत परंपरागत रूप से शासकीय अभिजात्य अथवा सवर्ण प्रभु वर्ग के हाथ में रही है जिसने प्राचीन काल से ही अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए निजी और सामाजिक शुचिता तथा पूर्वजन्म, कर्म फलवाद पर आधारित वर्ण व्यवस्था का सहारा लिया है। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से ब्राह्मणों ने सामाजिक सत्ता से लेकर राजनीतिक सत्ता तक का वितरण इस प्रकार किया कि समाज का बहुसंख्यक हिस्सा मानवीय गरिमा और मनुष्य के रूप में जीने तक के अधिकार से वंचित कर दिया गया। वर्णाश्रम व्यवस्था में जाति व्यवस्था के जरिए दलितों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शोषण को धार्मिक मानवीय और नैतिक ठहराया गया।"[1]

---

[1] राजकिशोर : दलित राजनीति की समस्याएं, पृ. 139

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने दलित समाज के लिए राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेस में पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग की। जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन चुनाव का अधिकार मिल गया। लेकिन इसी पृथक निर्वाचन को लेकर बाबासाहेब का गांधीजी से मतभेद हुआ। इस पूरी प्रक्रिया से दलितों की राजनैतिक शक्ति एवं प्रतिष्ठा बनी जिसके सहारे वे अपने वैध अधिकारों की मांग को आगे बढ़ा पाए।

दलितोत्थान में दलितों के राजनैतिक अधिकार दिलाने के लिए डॉ. बाबासाहेब ने प्रयास ही नहीं किया बल्कि प्रयोग करने के लिए "इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी" का गठन 1935 में किया। "इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी" ने तातकालीन बंबई प्रांत में चुनाव लड़ा क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र बंबई प्रांत था। आम चुनावों में इस दल ने दलित वर्गों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 सीटों पर विजय प्राप्त की और दो अन्य सामान्य सीटें भी जीतीं।[2] इस छोटे से प्रयोग से दतिलों में एक राजनैतिक चेतना दिखाई पड़ती है। सन् 1942 में "शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन" का गठन किया गया। इस पार्टी के माध्यम से बाबासाहेब दलितों को अखिल भारतीय स्तर पर संगठित कर उन्हें पृथक राजनैतिक अस्मिता प्रदान करने के लिए जुट गए। इस तरह से बाबासाहेब ने दलितों में राजनैतिक सत्ता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए बीज बो दिया था। इसके बाद संविधान के अंतर्गत बाबासाहेब ने दलितों के इन राजनैतिक अधिकारों को और भी बल प्रदान किया जाना था। परंतु 6 दिसंबर 1956 को बाबासाहेब का परिनिर्वाण हो गया और फिर सन् 1957 में दलित आत्मनिर्भर राजनीति की एक अन्य शाखा के रूप में महाराष्ट्र में ही रिपब्लिकन पार्टी का उदय हुआ। लेकिन बाबासाहेब अंबेडकर के

---

[2] कन्हैयालाल चंचरीक : आधुनिक भारत का दलित आंदोलन, पृ.188, 189

समय जो राजनीतिक चेतना का विकास दलितों में हो रहा था वह अवरूद्ध हो गया।[3]

इस तरह से कुछ वर्षों के लिए दलित राजनीति का आंदोलन स्वार्थी दलित नेताओं के कारण विफल हो गया। इसके बाद मान्यवर कांशीराम ने एक सशक्त कैडर खड़ा किया। पहले उन्होंने 'बामसेफ' बनाई। फिर 'डी.एस. फोर' का गठन किया। जिसकी देश के कोने-कोने में दलित बहुजन पाकिट्स में धूम मच गई। लगभग एक दशक तक 1973 से 1984 तक कांशीराम जी अकेले ही जुझते रहे। दलितों और पिछड़े वर्गों में नई जागृति और अधिकारों के प्रति सावधान रहने का पाठ पढ़ाते रहे। वे पत्र-पत्रिका, अखबारों एवं रैलियों के माध्यम से दलितों में राजनैतिक चेतना जागृत कर रहे थे और उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को "बहुजन समाज पार्टी" की स्थापना की जिसमें मायावती को बसपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और उत्तर प्रदेश में लोक सभा के कई उपचुनाव और चुनाव लड़े सफलता भी हासिल की।

दलित समाज में राजनैतिक चेतना जागृत करने वाली भारत की एक मात्र राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने उपेक्षित अधिकार वंचितों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की पार्टी है। सन् 1989 के आते-आते "बहुजन समाज पार्टी" पूरे भारत में अपनी छवि बना चुकी थी। कांशीराम का कहना था कि बिना राजसत्ता पर नियंत्रण पाए सामाजिक विकास संभव नहीं है। राजसत्ता ही सभी सामाजिक परिवर्तनों की मास्टर चाबी है ऐसा उनका मानना है इस तरह दलित राजनीति में "बहुजन समाज पार्टी" ने अपना प्रयोग "उत्तर प्रदेश" में किया जिसका परिणाम 1991 से लेकर आज तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चार बार सत्ता हासिल कर चुकी है।

---

[3] कन्हैयालाल चंचरीक : आधुनिक भारत का दलित आंदोलन, पृ. 361

मैंने अपने इस शोध के अध्याय एक में 'शोध का उद्देश्य', 'अध्ययन का महत्व', 'शोध प्रविधि' एवं शोध की परिकल्पनाएं को दर्शाया है। जिसमें मैंने शोध के दौरान जिन प्रविधियों का प्रयोग किया है उसे मैंने दर्शाया है। मेरा अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश था जिसमें मैंने प्राथमिक एवं व्दितीयक स्रोतों के माध्यम से इस शोध को पूरा किया है।

व्दितीय अध्याय "दलित और राजनीति" में मैंने 'दलित : शब्द का अर्थ एवं परिभाषा' जिसमें मैंने यह बताने की कोशिश की है की दलित शब्द का अर्थ क्या है और दलित को इस वर्तमान समय में किस परिप्रेक्ष में परिभाषित किया गया है। 'राजनीति से आशय' इसमें मैंने यह दिखने की कोशिश की है की राजनीति क्या है इसको डॉ. अंबेडकर एवं कांशीरम जी जैसे विद्वानों ने दलित समाज के लिए राजनीति में आना महत्वपूर्ण क्यों समझा है। 'दलित और राजनीति' जिसमें मैंने यह दिखने की कोशिश की है की दलित राजनीति की शुरुवात कब से शुरू होती है किस तरह से दलित समाज ने क्षेत्र में कदम रखा और राजनीति में उनकी किया भूमिका रही है।

अध्याया तीन "उत्तर प्रदेश के दलितों की स्थिति" इस अध्याय में मैंने 'सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति', 'आर्थिक स्थिति' एवं 'धार्मिक स्थिति' को जानने के लिए 29 प्रश्नों की अनुसूची बनाकर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को चयनित करके दलित बस्तियों में जाकर 100 दलित उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया है जिसमें मैंने वर्तमान समय में दलित समाज की 'सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति', 'आर्थिक स्थिति' एवं 'धार्मिक स्थिति' स्थिति किस तरह की है जिसमें मैंने साक्षात्कार के साथ ही साथ अवलोकन भी किया है तथा सामूहिक परिचर्चा भी की है। जिसे मैंने अध्याय में दर्शाया है।

अध्याय चार “उत्तर प्रदेश के दलितों का राजनीतिक उत्थान” इस अध्याय में ‘बसपा के पूर्व स्थिति’ दलित समाज की राजनैतिक स्थिति बसपा के पूर्व क्या थी और राजनीति में किस तरह से आए। ‘बसपा का उदय’ बसपा का उदय कैसे हुआ राजनैतिक मंच कैसे तैयार हुआ जिसको मैंने विश्लेषित किया है। ‘संसदीय चुनावों में दलितों की भागीदारी एवं बसपा’ इसमें मैंने यह दिखाया है की 1989 से लेकर 2009 तक के संसदीय चुनाव परिणाम में दलित लोगों के नामांकन एवं दलित मतदाताओं के मतदान एवं बसपा ने सुरक्षित एवं सामान्य शीटें पर कितनी सफलता प्राप्त की है शीटों की संख्या एवं मत प्रतिशत में क्या स्थिति रही है जिसे मैंने तालिका के माध्यम से दिखाया है। ‘विधान सभा चुनाव में दलितों की भागीदारी एवं बसपा’ इसमें मैंने 1989 से लेकर 2007 तक के विधान सभा चुनाव परिणाम में दलित लोगों के नामांकन एवं दलित मतदातों के मतदान एवं बसपा ने सुरक्षित एवं सामान्य शीटों पर कितनी सफलता प्राप्त की है शीटों की संख्या एवं मत प्रतिशत में क्या स्थिति रही है जिसे मैंने तालिका के माध्यम से दिखाया है।

मेरे शोध की जो परिकल्पनाएं थी जिसे मैंने शोध के माध्यम से जाँचने ने की कोशिश की है जिसके माध्यम से में अपने निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। शोध को और अच्छी तरह से करने के लिए मैंने सुझाव भी दिया है। समय सीमा कम होने के कारण शोध विषय के काफी पहलुओं को मुझे छोड़ना पड़ा है। जिसे पूरा करने के लिए इस विषय पर शोध करने की और आवश्यकता है।